

आर्थिक वृद्धि पर संदेह करने वाले ‘वक्रदृष्टा’: अमित शाह

यूपी ट्रेड शो में 90 देशों के 600 विदेशी खरीदारों के शामिल होने की उम्मीद

वीरेंद्र सिंह रावत

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार सुबह ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) 2026 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करते हुए देश की आर्थिक वृद्धि के आंकड़ों पर संदेह जताने वालों को 'वक्रदृष्टा' यानी नकारात्मक सोच रखने वाले लोग बताया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की 'डबल इंजन सरकार' की भी सराहना की। शाह ने कहा कि 2017 से पहले राज्य में जगह-जगह बने अवैध हथियार कारखानों की जगह अब छह विश्वस्तरीय विनिर्माण केंद्रों वाला बड़ा रक्षा औद्योगिक गलियारा विकसित किया गया है।

शाह ने कहा कि यह बदलाव 'डबल इंजन सरकार' के तहत हुआ है और आज उत्तर प्रदेश देश-विदेश के निवेशकों के लिए एक प्रमुख निवेश केंद्र बन रहा है। शाह पांच दिन चलने वाले इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे और इस समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। शाह ने कहा कि हाल की तिमाही में भारत की 7.8 फीसदी आर्थिक वृद्धि इस बात का सबूत है कि देश बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अब भी सबसे तेजी से बढ़ रहा है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, 'दुनिया में उथल-पुथल और कई चुनौतियों के बावजूद भारत ने अपना विकास जारी रखा है और इसे आगे बढ़ाया है।'

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में बनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पाकिस्तान की रातों की नींद हराम कर देती है। अमेठी में बनी एके-203 असॉल्ट राइफल 'नक्सलियों और आतंकवादियों' के खिलाफ एक प्रमुख हथियार बन गई है। उन्होंने कहा कि 'अपराध के पहले के माहौल से रक्षा निर्माण, वाहन उत्पादन और चिकित्सा-उपकरण निर्माण के क्षेत्र में परिवर्तन' उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है।

चौथे यूपीआईटीएस में में 90 देशों के 600 से अधिक विदेशी खरीदार भाग ले रहे हैं। साथ ही इसमें भाग रहे 2,400 से अधिक कारोबारी या कंपनियां अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। 25 से 29 सितंबर तक चलने वाले इस



केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य

आयोजन में 1.5 लाख से अधिक बिजनेस-टु-बिजनेस (बी2बी) आगंतुकों के आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि पांच दिन के इस आयोजन में 2025 के मुकाबले अधिक लोग पहुंचेंगे। 2025 के संस्करण में करीब 5 लाख लोग शामिल हुए थे और 400 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर भी हुए थे।

शाह ने कहा कि भारत ने वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद न केवल अपनी आर्थिक वृद्धि को बनाए रखा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे और मजबूत भी किया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने देश की विकास दर के अनुमान को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। केंद्रीय गृहमंत्री ने जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (जेसीआर) द्वारा भारत की संप्रभु रेटिंग को हाल में बढ़ाए जाने का भी उल्लेख किया।

उन्होंने विपक्षी दलों और कुछ विशेषज्ञों की भारत के आर्थिक प्रदर्शन की आलोचना को लेकर निंदा की, जिसमें पहली तिमाही में दर्ज की गई 7.8 फीसदी वृद्धि भी शामिल है। शाह ने कहा, 'कुछ 'वक्रदृष्टा' सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों पर विवाद करते रहते हैं। जिनकी सोच ही मरी हुई है, वे जीवंतता नहीं देख सकते, उन्हें हर जगह सब कुछ मृत ही नजर आजा है।' यह कहते हुए उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 31 जुलाई 2025 के उस बयान का शरारा किया, जिसमें कांग्रेस नेता ने दावा किया था कि 'भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है' और एक्स पर एक पोस्ट में पीएम पर इसे 'मारने' का आरोप लगाया था।

केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत की ओर से किए गए और जिन देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत चल रही है, उनका भी जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि इन समझौतों से भारतीय कारोबारियों के लिए निर्यात के नए अवसर खुले हैं। शाह ने निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि 2013 में उत्तर प्रदेश की खराब कानून-व्यवस्था के कारण लाखों नए निवेश सम्मेलन आयोजित नहीं हो सका था और इसे दिल्ली में आयोजित करना पड़ा था। शाह ने कहा, 'निवेश आकर्षित करने के लिए बेहतर औद्योगिक नीति, सक्रिय सरकार और उद्योग के अनुकूल रवैया जरूरी है। आज ये सभी स्थितियां उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और राज्य ने एक लाख करोड़ डॉलर की इकॉनमी बनने का लक्ष्य रखा है।'

कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपीआईटीएस का चौथा संस्करण 'नए उत्तर प्रदेश' की क्षमता को देखने का मौका देता है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में पारंपरिक कौशल को तकनीक, निवेश और वैश्विक बाजारों से जोड़कर राज्य की पहचान बदली है। उन्होंने कहा, 'उत्तर प्रदेश में क्षमता की कभी कमी नहीं रही। जरूरत सिर्फ इसकी पहचान करने, सही माहौल तैयार करने और इसे बड़े स्तर तक ले जाने की थी।' मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्सप्रेसवे, हाईवे, हवाई अड्डे, माल ढुलाई गलियारे और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे विकास कार्यों से राज्य में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे निवेश, उत्पादन और वैश्विक बाजारों तक पहुंच के नए अवसर पैदा हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला, एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल ने पारंपरिक कारोबार को एक अलग पहचान दिलाई है और उत्तर प्रदेश

को विनिर्माण केंद्र बनाने में मदद की है। उन्होंने कहा कि राज्य अब दुनिया के अलग-अलग बाजारों में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का सामान निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले यूपीआईटीएस में 75 देशों के 550 खरीदार शामिल हुए थे। इस साल करीब 90 देशों के खरीदारों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें 600 से अधिक विदेशी खरीदार होंगे। आयोजन में करीब 1.5 लाख बी2बी आगंतुकों के आने की भी उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान, रूस, वियतनाम, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और बेलारूस इस आयोजन में साझेदार देशों के रूप में शामिल हैं। उन्होंने कहा, 'इन देशों के पवेलियन से रणनीतिक साझेदारी, तकनीक के आदान-प्रदान और संयुक्त उद्यम के अवसर मिलेंगे।'

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से उत्तर प्रदेश के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। इससे राज्य विदेशी कंपनियों को यहां निवेश और उत्पादन के लिए आर्मांत्रित कर सकता है, ताकि वे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर सकें। आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार ने ओडीओपी, पोषक विश्वकर्मा और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के जरिए पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वैश्विक बाजार से जोड़ने का काम किया है।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अभी 79 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग मिला हुआ है। इसके अलावा 75 और उत्पादों के लिए आवेदन किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने भदोही के कालीन, मुरादाबाद के पीतल के सामान, कन्नौज के इत्र और वाराणसी की रेशमी साड़ियों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ट्रेड शो से कारीगरों को विदेशी खरीदारों से सीधे जुड़ने और बिचौलियों पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल रही है।

उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि आयोजन में 2,400 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें रक्षा, कृषि, उद्योग, ई-कॉमर्स, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), शिक्षा, बुनियादी ढांचा, चिकित्सा सेवाएं, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, डेरी, हथकरघा, कपड़ा और विभिन्न जीआई उत्पाद प्रमुख आकर्षण हैं।

राजग सहयोगियों ने मांगा स्पष्टीकरण

भाजपा के तीन सहयोगी दलों लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) ने शुक्रवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव व्यवस्था पर लोगों का भरोसा दांव पर है। पासवान लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि वह न तो चुनाव आयोग के लिए बोल रहे हैं और न ही विपक्ष के आरोपों का समर्थन कर रहे हैं लेकिन उन्होंने कहा कि जनता के सामने अब जो सवाल हैं, उनके लिए आयोग से स्पष्ट प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी तत्काल स्पष्टीकरण की मांग की, जबकि टीडीपी के लोकसभा फ्लोर लीडर लावु श्रीकृष्णा देवरायालू ने कहा कि पारदर्शिता संवैधानिक संस्था में विश्वास को मजबूत करने में मदद करेगी। इनकी टिप्पणियां 'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित एक रिपोर्ट के



बाद आई, जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार उन निर्णयों और आदेशों पर लिखित आपत्ति जताई है, जिन्हें उन्होंने उनकी जानकारी या सिफारिश के बिना जारी किया गया बताया था।

इन आपत्तियों में वैधानिक मतदाता पंजीकरण फॉर्म 6 में बदलाव, मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया का प्रबंधन और मतदाता सूची के डेटाबेस पर केंद्रीकृत नियंत्रण से जुड़े मामले शामिल थे। इस रिपोर्ट के बाद विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और मतदाता सूची के एसआईआर को रोकने की

मांग की है। पासवान ने संवाददाताओं से कहा, 'मैं यह स्पष्ट कर दूं कि सरकार के एक हिस्से के रूप में मेरा इरादा किसी संवैधानिक निकाय का बचाव करना नहीं है। मैं विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में भी बहुत चिंतित नहीं हूं, जो हमेशा वही रख अपनाएगा जो राजनीतिक रूप से उसके लिए फायदेमंद हो।' उन्होंने कहा, 'यदि लोग चुनावी प्रणाली में विश्वास खोना शुरू कर देते हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा और इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को अपना स्पष्टीकरण अधिक मजबूती से देनी चाहिए। उसे राहुल गांधी और उनके सहयोगियों की बातों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन उसे

लोगों के मन से गलतफहमियों को दूर करना चाहिए।' टीडीपी के देवरायालू ने कहा कि हालांकि आंध्र प्रदेश में एसआईआर पारदर्शी तरीके से आयोजित किया गया था, चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण फायदेमंद होगा। उन्होंने कहा, 'आंध्र प्रदेश के दृष्टिकोण से एसआईआर अभ्यास को करीब से देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की गई थी। हर मतदाता को भाग लेने और चिंताएं उठाने के लिए पर्याप्त अवसर और पर्याप्त समय प्रदान किया गया था।' उन्होंने कहा, 'अभ्यास सफल रहा है। यहां तक कि विपक्ष भी आंध्र प्रदेश में प्रक्रिया के संबंध में चिंताओं को सही साबित नहीं कर पाया है। साथ ही, भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसे हमारे लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसलिए, जब भी किसी के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं, तो उचित स्पष्टीकरण प्रदान करने और पारदर्शिता बनाए रखने से संस्था में जनता का विश्वास मजबूत होगा।' **एजेंसियां**

PUBLIC ANNOUNCEMENT

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

(Please scan the QR code to view the DRHP)

BULLS EYE KNOWLEDGE SYSTEM LIMITED

Our Company was incorporated as a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated March 13, 2013 issued by the Registrar of Companies, Punjab and Chandigarh at Chandigarh. Subsequently, pursuant to a resolution passed by our Board of Directors in their meeting held on June 30, 2024 and by our Shareholders in an Extraordinary General Meeting held on June 30, 2024, our Company was converted into a public limited company, consequently our name was changed to "Bulls Eye Knowledge System Limited" and a fresh certificate of incorporation dated September 25, 2024 was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre. The corporate identification number of our Company is U80903CH2013PLC034370. For further details of change in name and registered office of our company please refer to the chapter titled, "History and Certain Corporate Matters" on page 196 of the Draft Red Herring Prospectus.

Registered Office: SCO 91-92 Front Portion, Second Floor Sector 8-C, Chandigarh, 160 009 India | **Tel:** +91 623 950 0393.
Corporate Office: Plot No E-305, Phase 8A, Industrial Area Focal Point S.A.S. Nagar, Mohali - 160 055, Punjab, India. | **Tel:** +91 842 200 0037
Website: www.hitbullseye.com | **E-mail:** cs@hitbullseye.com | **Corporate Identity Number:** U80903CH2013PLC034370
Contact Person: Srishti, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: HIRDESH MADAN, DEEPAK KUMAR, AND SANJAY KUMAR

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 20,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF BULLS EYE KNOWLEDGE SYSTEM LIMITED ("OUR COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE"), AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS COMPRISING A FRESH ISSUE OF UPTO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS BY OUR COMPANY (THE "ISSUE") WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF UPTO [●] EQUITY SHARES AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS IS HEREAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE [●]% AND [●]%, RESPECTIVELY OF THE POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

ATTENTION PUBLIC

This is to inform that the Company has filed Draft Red Herring Prospectus (DRHP) dated September 24, 2026, with the SME platform of the BSE Limited (BSE SME), on September 25, 2026, in respect of the proposed IPO of the Company in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations, 2018 (IPO of Small and Medium Enterprises).

This public announcement is made in compliance with the Regulation 247(2) of the SEBI ICDR Regulations, 2018, which requires the draft offer document shall be made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days, from the date of such filing by hosting it on the website of the exchange, the Issuer and the BRLM. Accordingly, it may be noted that the DRHP dated September 24, 2026 filed by the Company is hosted on the website of the BSE at www.bseindia.com, and the website of the Company at www.hitbullseye.com, and at the website of BRLM i.e. Horizon Management Private Limited at www.horizonmanagement.in. Our Company hereby invites the members of the public to give their comments to Stock Exchange, to Company Secretary and Compliance Officer of our Company and /or the BRLM at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by BSE SME and/or our Company and/or BRLM in relation to the issue on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing the Draft Red Herring Prospectus (i.e. September 25, 2026) with SME Platform of the BSE Limited (BSE SME).

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and this Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of this DRHP. Specific attention of the investors is invited to the section titled "Risk Factors" beginning on page 24 of the Draft Red Herring Prospectus.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be taken after the Red Herring Prospectus (RHP) has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in the RHP from the DRHP. The Equity Shares, when offered through the Prospectus, are proposed to be listed on the BSE SME.

For details of the main objects of the Company as contained in its Memorandum of Association, please refer to the section titled "Our History and Certain other Corporate Matters" beginning on page 194 of the Draft Red Herring Prospectus. The liability of the members of the Company is limited. For details of the share capital and capital structure of the Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them, please refer to the section titled "Capital Structure" beginning on page 77 of the Draft Red Herring Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS	REGISTRAR TO THE OFFER
HORIZON MANAGEMENT PRIVATE LIMITED 19 R N Mukherjee Road, Main Building, 2nd Floor, Kolkata - 700 001, West Bengal, India. Telephone: +91 33 4600 0607 E-mail: smelpo@horizon.net.co Website: www.horizonmanagement.in Investor grievance: investor.relations@horizon.net.co SEBI Registration Number: INM000012926 Contact Person: Narendra Bajaj	MAASHITLA SECURITIES PRIVATE LIMITED 451, Krishna Apra Business Square, Netaji Subhash Place, Pittampura - 110034, Delhi, India Tel: 114 758 1432 Email: ipo@maashitla.com Website: www.maashitla.com Investor Grievance Email ID: investor.ipo@maashitla.com SEBI registration number: INR000004370 Contact Person: Mukul Agrawal
COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER	
BULLS EYE KNOWLEDGE SYSTEM LIMITED Srishti, Company Secretary and Compliance Officer SCO 91-92 Front Portion, Second Floor Sector 8-C, Chandigarh - 160 009, India. Tel. No.: +91 623 950 0393 Email: cs@hitbullseye.com Website: www.hitbullseye.com	
Investors can contact our Company Secretary and Compliance Officer, Book Running Lead Manager or Registrar to the Issue, in case of any pre issue or post issue related problems, such as non- receipt of letter of allotment, non- credit of allotted Equity shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc.	

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For BULLS EYE KNOWLEDGE SYSTEM LIMITED
On behalf of the Board of Directors

Sd/-
Srishti
Company Secretary and Compliance Officer

Bulls Eye Knowledge System Limited is proposing, subject to, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public issuance of its Equity Shares and has filed the DRHP dated September 24, 2026 with BSE SME. The DRHP shall be available on the website of the BSE at www.bseindia.com, and the website of the Company at www.hitbullseye.com, and at the website of BRLM i.e. Horizon Management Private Limited at www.horizonmanagement.in., respectively. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see "Risk Factors" of the RHP, when available. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" beginning on page 24 of the DRHP.

The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where such offers and sales are made. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

AdBaz

ट्राई ने शुरू किया इनडोर डेटा कनेक्टिविटी रेटिंग प्लेटफॉर्म

गुलवीन ओलख

भारतीय दूरसंचार नियामक (ट्राई) ने शुक्रवार की 'डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग प्लेटफॉर्म' शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपभोक्ता, प्रॉपर्टी डेवलपर और संपत्ति के मालिक इमारतों की डिजिटल कनेक्टिविटी की रेटिंग देख सकेंगे। नियामक ने इमारतों के अंदर डिजिटल कनेक्टिविटी जांचने के लिए एक ऐप भी शुरू किया है, जो बेहद अहम है क्योंकि आजकल लगभग 70-80 फीसदी मोबाइल डेटा का उपयोग घरों और दफ्तरों के अंदर होता है।

ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने शुक्रवार को कहा, 'डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत संपत्ति के भीतर डिजिटल कनेक्टिविटी को अधिक मापने योग्य, पारदर्शी और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बेहतर योजना बनाने, हितधारकों के बीच तालमेल में सुधार करने और उपभोक्ताओं को संपत्तियों की कनेक्टिविटी ढांचा और प्रदर्शन के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने में सहायता करेगा।' यह प्लेटफॉर्म घरों, दफ्तरों, संस्थाओं और सार्वजनिक स्थानों के भीतर कनेक्टिविटी की गुणवत्ता को डिजिटल

कनेक्टिविटी अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग प्लेटफॉर्म ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। इसमें उपभोक्ताओं को कनेक्टिविटी की जानकारी देने के साथ साथ डिजिटल कनेक्टिविटी जांचने के लिए एक मोबाइल ऐप

डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण है क्योंकि 70-80 फीसदी डेटा खपत घरों के अंदर



भी उपलब्ध है। यह प्लेटफॉर्म रेटिंग की पूरी प्रक्रिया के लिए एक एकीकृत डिजिटल इंटरफेस प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म पोर्टल और ऐप दोनों के रूप में काम करेगा। इसका इस्तेमाल संपत्ति प्रबंधक और ग्राहक दोनों कर सकेंगे। रेटिंग एक से पांच स्टार के स्तर पर होगी, जिसमें एक स्टार सबसे कम और पांच स्टार सबसे अधिक रेटिंग को दर्शाएगा। नियामक ने निर्माणाधीन संपत्ति के लिए आधे स्टार की रेटिंग का विकल्प भी रखा है।

संपत्ति प्रबंधक इस प्लेटफॉर्म पर अपना और संपत्ति का पंजीकरण कर सकते हैं, रेटिंग के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं, जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, पंजीकृत डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी का चयन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग

एजेंसी (डीसीआरए) पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकती है। वे उन्हें आवंटित संपत्ति की जानकारी देख सकेंगे, उसका आकलन कर सकेंगे, अपनी टिप्पणियां और टेस्ट के नतीजे दर्ज कर सकेंगे और जरूरी दस्तावेज प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकेंगे। संपत्ति का मौके पर

आकलन डीसीआरए के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप के जरिये किया जाएगा। अधिकृत डीसीआरए इस ऐप का इस्तेमाल तब जांच प्रक्रिया के अनुसार इमारत के भीतर डिजिटल कनेक्टिविटी की जांच के लिए कर सकेंगे।

नियामक ने कहा कि ग्राहकों के लिए प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रेटिंग सच पेज उपलब्ध होगा। यहां उपभोक्ता संपत्ति के नाम या स्थान के आधार पर उसकी रेटिंग खोज सकेंगे। इससे उन्हें इमारत की डिजिटल कनेक्टिविटी के आधार पर खरीद या किराये का फैसला लेने में मदद मिलेगी। नियामक ने कहा कि इससे घर या संपत्ति खरीदने और किराये पर लेने के फैसलों में मदद मिलेगी। मोबाइल ऐप के जरिये किए गए डिजिटल कनेक्टिविटी टेस्ट का विवरण प्लेटफॉर्म पर अपने आप दर्ज हो जाएगा।

यह प्लेटफॉर्म तैयार हो चुकी और निर्माणाधीन दोनों तरह की संपत्तियों की रेटिंग की सुविधा देता है। निर्माणाधीन संपत्तियों के लिए चरणबद्ध प्रमाणन की व्यवस्था है। इसमें डिजिटल कनेक्टिविटी ढांचे की डिजाइन और योजना, उसकी स्थापना की जांच और निर्माण पूरा होने के बाद टेस्टिंग के आधार पर अंतिम ग्रेड या रेटिंग प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

हितधारक सार्वजनिक इंटरफेस के माध्यम से रेटेड संपत्तियों की खोज कर सकेंगे, उनकी प्रकाशित रेटिंग देख सकेंगे और संबंधित प्रमाण पत्रों को सत्यापित भी कर सकेंगे। यह प्लेटफॉर्म 2024 में जारी डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग (डीसीआर) फ्रेमवर्क के आधार पर काम करता है। इसमें फाइबर की उपलब्धता, मोबाइल नेटवर्क, इमारत के अंदर कनेक्टिविटी और वाई-फाई ढांचे जैसे मापदंडों के आधार पर डिजिटल कनेक्टिविटी और संपत्ति के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है।